

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिसांसिबिलिटी है

योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर !

'इस वीडियो ने अंतरात्मा को झकझोर दिया'

■ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों को फटकारा

■ जिनके घर गिराए उनको देना होगा 10 लाख का मुआवजा

एजेंसी | नई दिल्ली

इस प्रतीकात्मक तस्वीर का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। बुलडोजर एक आशियाने को रौंद रहा था और एक बच्ची उस टूट रही झोपड़ी से अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। यह अन्याय इतिहास में सबसे सियाह शब्दों में दर्ज हो चुका है। अब इस वीडियो ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को अंदर तक हिला दिया।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्राधिकरण (PDA) को पांच याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने अपनी

टिप्पणी में कहा कि अफसरों में संवेदनशीलता नहीं है। ये मकान कानून की प्रक्रिया का पालन किए बगैर गिराए गए थे। इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा हिला दी है। घरों पर बुलडोजर चलने की ये घटना 2021 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के तहत नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन माना। कोर्ट ने कहा कि नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर घर गिराने की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध थी। कोर्ट ने इसे समाज में गलत संदेश फैलाने वाली और कानून के शासन के खिलाफ कार्रवाई करार दिया।

ढहती झोपड़ी से भाग रही बच्ची के वीडियो का दिया हवाला

जस्टिस अभय ओका और जस्टिस पन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मुआवजा प्रभावितों को राहत देने के साथ साथ सरकार को भविष्य में इस तरह की मनमानी रोकने के लिए भी है। फैसले के दौरान कोर्ट ने हाल में वायरल एक वीडियो का हवाला भी दिया। इस वीडियो में बुलडोजर एक्शन के दौरान एक बच्ची अपनी किताबें लेकर ढहती झोपड़ी से भागती दिख रही है। कोर्ट ने इसे अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया।

15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य

कोर्ट ने पहले के दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया जिसमें किसी संपत्ति को ध्वस्त करने से पहले 15 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर घर दोबारा बनाने की अनुमति दी लेकिन कहा कि अगर उनकी अपील खारिज होती है तो उन्हें निर्माण हटाना होगा।

न्यूज ड्रॉफ

वक्फ बिल पर सदन में तकरार तय



नई दिल्ली। विपक्षी दलों इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर गठबंधन के नेताओं ने अहम बैठक की और तय किया कि इस बिल का हर स्तर पर कड़ा विरोध किया जाएगा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे इस बिल को असंवैधानिक मानते हैं और इसे किसी भी हाल में पारित नहीं होने देंगे।

कुणाल कामरा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत

चेन्नई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बिना उनका नाम लिए व्यंग्य करने के बाद विवादों में घिरे स्टैंडअप कर्मीडियन कुणाल कामरा को तमिलनाडु के वनूर में जिला मजिस्ट्रेट-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। कामरा ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। यह उस क्षेत्राधिकार से अलग क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है, जहां एफआईआर दर्ज की गई है।

महंगाई का डोज

संक्रमण, मधुमेह की बीमारी समेत 900 दवाइयों के दाम बढ़े

नई दिल्ली। देश में 1 अप्रैल से गंभीर संक्रमण, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों की दवाइयों के दाम बढ़ गए। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने मंगलवार से 900 से अधिक जरूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक, प्राधिकरण ने कीमतों में 1.74 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की। इन दवाइयों के महंगी होने का असर आम नागरिकों पर पड़ने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन की 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की अधिकतम कीमत क्रमशः 11.87 और 23.98 रुपये टैबलेट होगी। वहीं एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलैनिक एसिड वाले ड्राई सिरप की कीमत 2.09 रुपये तय की गई है। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की कीमत 6.47 रुपये से बढ़कर 14.04 रुपये होगी। दर्द में खाई जाने वाली दवा डाइक्लोफेनोक की अधिकतम कीमत अब 2.09 रुपये प्रति टैबलेट होगी। दरअसल, दवा निर्माता डब्ल्यूपीआई के आधार पर अधिकतम खुदरा कीमतें बढ़ा सकते हैं और इसके लिए केंद्र की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दौड़ेंगी बाइक टैक्स

▶▶ बाइक टैक्स नीति को दी अपनी मंजूरी

▶▶ फडणवीस कैबिनेट में लिया गया निर्णय

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई और इससे सटे ठाणे समेत दूसरे तमाम शहरों के साथ राज्य में अब 'बाइक टैक्स' दौड़ेंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 'बाइक टैक्स' चलाने को स्वीकृति दे दी गई। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा बाइक टैक्स नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब परिवहन के इस नए किफायती विकल्प के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।



बाइक टैक्स सिर्फ 20 से 50 वर्ष की आयु के चालक ही चला सकेंगे। इसके अलावा, महिला यात्रियों को महिला चालक चुनने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अकेले मुंबई में ही दस हजार से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। प्रताप सरनाईक ने विधेयक व्यक्त किया कि

बाइक पूलिंग को स्वीकृति

राज्य सरकार ने सड़क पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए, सरकार ने निजी दोपहिया वाहनों के लिए बाइक-पूलिंग के विकल्प को भी मंजूरी दी है। इन वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, वैध परमिट और बीमा अनिवार्य होगा। बाइक टैक्स किराया दरें संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

कौन चला पाएगा?

सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अकेले मुंबई में ही दस हजार से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। प्रताप सरनाईक ने विधेयक व्यक्त किया कि

कम खर्च में पूरा होगा सफर

बाइक टैक्स सेवा से कम खर्च में सुगम यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति के तहत, केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्स परिवहन सेवा में शामिल की जाएगी। यह योजना नागरिकों को सस्ता परिवहन विकल्प और 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' प्रदान करेगी। इसके साथ ही, यह शहरों में प्रदूषण और यातायात जाम को कम करने में मदद करेगी और यात्रा का समय घटेगा। साथ ही, नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

किराना दुकानों को राहत

अब 24 घंटे खुले रह सकती हैं किराना दुकानें

किराना दुकानों को 24 घंटे खुले रखने से नहीं रोकता कानून : कोर्ट

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 24 घंटे खुली रहने वाली किराना दुकानों को ग्राहकों और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद करार देते हुए कहा कि कानून के तहत इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया कि वह किसी भी सुविधा स्टोर को रात 11 बजे तक बंद करने के लिए बाध्य न करे।



डांस बार और हुक्का बार पर लागू होते हैं प्रतिबंध

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेटना की खंडपीठ ने कहा कि 24x7 सुविधा स्टोर की अवधारणा दुनियाभर में लोकप्रिय है और इससे उपभोक्ताओं को खरीदारी में सहूलियत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनके काम के

घंटे असामान्य होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि रात 11 बजे तक बंद करने का प्रतिबंध केवल हुक्का बार, डांस बार और शराब परोसने वाले रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों के लिए लागू होता है, किराना दुकानों के लिए नहीं।

स्पेशल स्टोरी

जंगल की जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध नजर

- ▶▶ दिल्ली, सिक्किम और गोवा के बराबर जंगलों पर अवैध कब्जा
- ▶▶ 25 राज्यों में अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र
- ▶▶ 13 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल अतिक्रमण की जद में

एजेंसी | नई दिल्ली

देश में दिल्ली, सिक्किम और गोवा के भौगोलिक क्षेत्र के बराबर जंगलों पर अवैध कब्जा हो रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इसके अनुसार, 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 13 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है।



बिहार, हरियाणा समेत कई राज्यों ने विवरण नहीं दिया

रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपना आंकड़ा पेश किया है, उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर तथा दमन और दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा,

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। वहीं लगभग 10 राज्यों ने वन अतिक्रमण पर डाटा या विवरण पेश नहीं किया। इसमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, नगालैंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं।

व्या कहते हैं आंकड़ें

- ▶ मध्य प्रदेश और असम सबसे अधिक प्रभावित
- ▶ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी को सौंपे आंकड़े
- ▶ 10 राज्यों ने वन अतिक्रमण पर आंकड़े पेश नहीं किए

एनजीटी ने वन अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लिया

दरअसल, पिछले वर्ष एनजीटी ने वन अतिक्रमण पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें बताया गया था कि भारत में 7,50,648 हेक्टेयर (या 7506.48 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है, जो दिल्ली के आकार से पांच गुना अधिक है। इस पर एनजीटी ने मंत्रालय को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्रों के अतिक्रमण का विवरण एक निर्धारित प्रारूप जमा करने का निर्देश दिया था। अब पिछले हफ्ते एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट में मंत्रालय ने बताया कि मार्च, 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13056 वर्ग किलोमीटर) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था। इसमें बताया गया कि राज्यों में सबसे अधिक मध्य प्रदेश और असम में सबसे अधिक वन अतिक्रमण है।

तीन श्रेणी में बंटा

दरअसल, वन क्षेत्र या रिजॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया (आरएफए) को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें आरक्षित वन, जिन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त है और जिनमें शिकार और चराई जैसी गतिविधियां आम तौर पर प्रतिबंधित हैं। आरएफए में सरकार उन जंगलों को भी वन के तौर पर नामित भूमि में रखा है, जिनमें पेड़ न भी हों।

प्रदेशों के साथ गत वर्ष 11 नवंबर को बैठक भी हुई। मंत्रालय ने इस साल 22 फरवरी और 26 मार्च को भी पत्र भेजे, जिसमें बचे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जानकारी देने को कहा गया है।

मुंबईकरों पर 'कचरा टैक्स'!

आदित्य टाकरे ने 'कचरा टैक्स' को बताया आम जनता पर बोझ

प्रपोजल प्रस्तावित, अंतिम मंजूरी नहीं

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

शिवसेना (UBT) नेता आदित्य टाकरे ने 'कचरा टैक्स' के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे मुंबईकरों पर अधिक बोझ बताया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर 'अप्रैल फूल सरकार' का तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ नए कर वसूलने में लगी है, जबकि जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप

आदित्य टाकरे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'कचरा टैक्स' से जनता की जेब काटी जा रही है, जबकि टैकेदारों की जेबें भरी जा रही हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार करे और आम जनता को राहत दे।

कैसे वसूला जाएगा कचरा टैक्स?

बुध-मुंबई नगर निगम ने सोमवार को 2025 के लिए स्वच्छता और सफाई नियम प्रस्तुत किया। जिसमें घरों से दैनिक कचरा संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता कर भी शामिल है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 50 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र (बीयूप) वाले आवासों से 100 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। जबकि, 50 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर के बीच बीयूप वाले आवासों के लिए 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। बीयूप में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले घरों के लिए कचरा संग्रहण शुल्क 1000 रुपये होगा। यह कर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैस्टहाउसों, रेस्तरां, क्लबों, प्रयोगशालाओं, गोदामों, कार्यालयों, लघु एवं कुटीर उद्योग कार्यशालाओं, शीतगृहों, विवाह हॉलों, उत्सव हॉलों, प्रदर्शनियों और सभा स्थलों पर भी लगाया जाएगा। फिलहाल इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, यह प्रपोजल प्रस्तावित है।

कार्रवाई कर अतिक्रमण भी हटाया

रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक 409.77 वर्ग किलोमीटर वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि मार्च, 2024 तक अतिक्रमण के तहत कुल वन भूमि से इस क्षेत्र

को बाहर रखा गया था या नहीं। मंत्रालय ने एनजीटी को बताया कि उसने पिछले साल 1 मई, 17 मई और 28 मई को भेजे पत्रों से राज्यों से डेटा जमा करने को कहा था। राज्यों और केंद्र शासित

रत्नागिरी में सड़क हादसे के बाद हंगामा

भीड़ ने ट्रक को किया आग के हवाले

डीबीडी संवाददाता | रत्नागिरी

रत्नागिरी जिले के खंडाला वाटड इलाके में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। इस घटना में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।



गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा

इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और निवाली-जयगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। हादसे से नाराज भीड़ ने मौके पर ही ट्रक में आग लगा दी।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार, खंडाला वाटड गांव के निवासी किरण पागडे मोटरसाइकिल से निवाली-जयगढ़ मार्ग पर किसी काम से जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे किरण पागडे की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

सूचना मिलते ही रत्नागिरी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने ट्रक में लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था।

ट्रक चालक गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने मृतक युवक किरण पागडे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दमकल कर्मियों ने ट्रक को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने गुस्साई भीड़ को शांत किया और अब आगे की जांच जारी है।

काम की खबर

ठाणे सिविल अस्पताल में आधुनिक एफेरेसिस मशीन की शुरुआत

डॉ. कैलाश पवार, सर्जन, ठाणे जिला सिविल अस्पताल

इस मशीन से मरीजों को प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की उपलब्धता में सुधार होगा। इस अवसर पर निरीक्षण के दौरान जिला शल्य चिकित्सक डॉ. कैलाश पवार, निवासी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मृणाल राहुद, डॉ. गिरीश चौधरी और विनोद जोशी मौजूद रहे।

डॉ. कैलाश पवार, सर्जन, ठाणे जिला सिविल अस्पताल



प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की कमी होगी दूर

डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में मरीजों के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है, जिससे रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बाधित होती है। आमतौर पर मरीजों के परिजनों को ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन एफेरेसिस मशीन की मदद से अब यह प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। ब्लड बैंक प्रमुख डॉ. गिरीश चौधरी ने बताया कि अब रक्तदाता के शरीर से केवल आवश्यक अवयव ही निकाले जाएंगे, जिससे बार-बार रक्तदान करने की जरूरत नहीं होगी।

कैसे काम करेगी एफेरेसिस मशीन?

सामान्य रक्तदान में 350 मिलीलीटर रक्त निकाला जाता है, जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा लगभग 5,000 होती है। एफेरेसिस मशीन से एक बार में 50,000 प्लेटलेट्स निकाले जा सकते हैं, जिससे मरीजों को जल्दी राहत मिलेगी। इस मशीन से प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं और अन्य रक्त घटक अलग करना संभव है। सामान्य रक्तदान के बाद तीन महीने बाद ही दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। एफेरेसिस मशीन से प्लेटलेट्स निकालने के बाद एक सप्ताह में दो बार भी प्लेटलेट्स दान करना संभव है।

मरीजों और दाताओं के लिए राहत

अब मरीजों के परिजनों को प्लेटलेट्स के लिए महंगे ब्लड बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही, इच्छुक दाताओं के लिए प्लेटलेट्स दान करना पहले से अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगा।

1570 करदाताओं ने पहले ही दिन जमा किया 1.80 करोड़ रुपये का संपत्ति कर

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

ठाणे नगर निगम (टीएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर का भुगतान 1 अप्रैल को करदाताओं से स्वीकार करना शुरू किया है। इसके तहत 1,570 जागरूक ठाणे करदाताओं ने पहले ही दिन 1.80 करोड़ रुपये का



संपत्ति कर जमा किया, जिससे नगर निगम को अच्छी शुरुआत मिली है।

संपत्ति कर संग्रहण केंद्र पर भी सुविधा

साथ ही, ठाणे के वार्ड कार्यालय स्थित संपत्ति कर संग्रहण केंद्रों पर भी संपत्ति कर जमा करने की सुविधा शुरू की गई है। नगर निगम ने यह भी जानकारी दी कि सभी करदाता सोमवार से शनिवार तक प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किसी भी संग्रहण केंद्र पर अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा

संपत्ति कर भुगतान के लिए नगर निगम ने करदाताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें करदाताओं को ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। एसएमएस में करदाताओं को संपत्ति कर डाउनलोड करने और प्रिंट करने का लिंक भी दिया गया है, जिससे वे इंटरनेट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

ठाणे जिला परिषद ने लू से बचने की अपील की

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

वर्तमान में बढ़ती गर्मी से ठाणे जिला में भी लोग परेशान हो रहे हैं। इस गर्मी से बचने के लिए ठाणे जिला परिषद ने नागरिकों से हीटस्ट्रोक (लू) से बचने की अपील की है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे और जिला स्वास्थ्य



अधिकारी डॉ. गंगाधर पारणे ने नागरिकों से आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है।

25 स्थानों पर अस्थायी पेयजल सुविधा शुरू

मनपा और सामाजिक संस्थाओं की गर्मी से राहत देने की पहल

धर्मेंद्र उपाध्याय | ठाणे

बढ़ती गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शहर के 25 स्थानों पर अस्थायी पेयजल सुविधा शुरू की है। यस चैरिटेबल ट्रस्ट, जेवीएम चैरिटेबल फाउंडेशन और समर्थ भारत ने इस पहल में सहयोग दिया है। इस सुविधा का उद्घाटन मंगलवार को ठाणे स्टेशन परिसर स्थित सेंटिस के नीचे किया गया।



गर्मी प्रबंधन के तहत विशेष योजना

शहर में बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती गर्मी को नियंत्रित करने के लिए पिछले वर्ष ठाणे के लिए एक व्यापक ताप प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। यह योजना महाराष्ट्र सरकार, मनपा और ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई थी।

आयुक्त सौरभ राव के

निर्देश पर जागरूकता अभियान

गर्मी से निपटने के लिए मनपा आयुक्त सौरभ राव के निर्देशानुसार महानगरपालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में सिचाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

किन-किन स्थानों पर सुविधा उपलब्ध

अस्थायी पेयजल सुविधा ठाणे स्टेशन, कोपरी ब्रिज, आइस फैक्ट्री, आशर आईटी पार्क, किसन नगर स्कूल,

एमआईडीसी-अंबिका नगर, हजुरी गांव, वाफा पार्क, अमृत नगर पुलिस चौकी-मुंबा, लोकमान्य डिपो, रबोडी नाका, वर्तक नगर कोर्ट नाका और शास्त्री नगर नाका समेत 25 प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है।

आमदार कुमार आयलानी ने किया मध्यवर्ती अस्पताल का दौरा

डॉक्टरों और कर्मचारियों से मुलाकात, समस्याओं के समाधान का आश्वासन

सुरेश चौहान | उल्हासनगर

आमदार कुमार आयलानी ने मंगलवार को मध्यवर्ती अस्पताल का दौरा किया और शल्य चिकित्सक डॉ. मनोहर बनसोडे व अन्य कर्मचारियों से मुलाकात कर अस्पताल से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि डॉक्टरों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वे उच्च अधिकारियों और शासन स्तर पर चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। आमदार कुमार आयलानी ने कहा कि मध्यवर्ती अस्पताल न केवल उल्हासनगर बल्कि कर्जत, कसारा जैसे ग्रामीण इलाकों के मरीजों के लिए भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र है।



डॉ. बनसोडे के कार्यों की सराहना

आमदार ने अस्पताल के मुख्य शल्य चिकित्सक डॉ. मनोहर बनसोडे की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अस्पताल में कई सकारात्मक परिवर्तन और विकास कार्य हुए हैं। इस अवसर पर डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा आमदार आयलानी का भव्य स्वागत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प का अनावरण

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के 90 वर्षों का ऐतिहासिक मील का पत्थर पूरा किया। इस महत्वपूर्ण अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए डाक विभाग ने आरबीआई के 90 वर्षों के प्रतीक चिह्न के साथ एक कस्टमाइज्ड 'माई स्टैम्प' का अनावरण किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और विरासत को दर्शाता है। यह कस्टमाइज्ड 'माई स्टैम्प' भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया जिनमें राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन,



मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल, महानिदेशक 'माई स्टैम्प' भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया जिनमें राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन,

महायुति के पूर्व नगरसेवकों ने की आयुक्त से मुलाकात

विकास कार्यों और समस्याओं पर हुई चर्चा

डीबीडी संवाददाता | उल्हासनगर

मंगलवार को महायुति के पूर्व नगरसेवकों और विधायक कुमार आयलानी ने मनपा आयुक्त मनीषा आन्हाले से मुलाकात कर शहर के विभिन्न विकास कार्यों और नागरिक समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया। बैठक में विधायक कुमार आयलानी ने पानी के बिल की अदायगी के लिए अभय योजना लागू करने, रेगुलराइजेशन प्रक्रिया को तेज



करने, अंडरग्राउंड सीवेज का काम जल्द पूरा कर कॉन्क्रिटकरण करने, सड़कों के गड्ढे भरने, रोड डिवाइडर का सुंदरीकरण और स्पीड ब्रेकर पर सफेद पट्टी लगाने, हॉक्स जॉन को चिन्हित करने, सीसीटीवी प्रोजेक्ट के लिए की जा रही खुदाई के बाद कॉन्क्रिटकरण करने जैसे मांगें रखीं।

इसके अलावा, सर्वे नंबर 188 पर डंपिंग ग्राउंड को हटाने, यूएमसी की संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने, आरोग्य केंद्रों पर नियमित दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने, मानसून से पहले नालों की सफाई करने और शहर में गार्डन विकसित करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

पानी और मंदिरों से जुड़े मुद्दे उठाए

विधायक कुमार आयलानी ने पानी के बिलों में बढ़ोतरी न करने की मांग की, जिसके जवाब में आयुक्त ने एक माह के भीतर इस पर निर्णय लेने की बात कही। साथ ही, जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित है, वहां निशुल्क पानी के टैंकर उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। इसके अलावा, विधायक ने सुझाव दिया कि मंदिरों को गरीब जनता की सहायता के लिए बनाया गया है, इसलिए नगर निगम को उनसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए।

अ. क्र.	निविदा क्रमांक	कामाचे नांव	निविदा रक्कम (जी.एस.टी वगळून)	इसारा रक्कम	कालावधी	वर्गवारी
		उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील मुलभूत सोयी सुविधांचा विकास योजनेअंतर्गत विविध कामे करणेबाबत.	४,०६,७७,९६६/-	२,२०,०००/-	१२० दिवस	NA
	१	उल्हासनगर ३ मधील स्मशान भूमी येथे सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	२	उल्हासनगर १ मधील स्मशान भूमी फकार मंडळी चौक जवळ सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	३	उल्हासनगर १ मधील झुलेताल मंदीर जवळ सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	४	उल्हासनगर १ मधील टिळक नगर चौदर टैक जवळ सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	५	डोवूराम दरवार जवळ सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	६	प्रभाग क्र. ११ मधील मधु कॉमप्लेक्स बरेक नं १००० मध्ये सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	७	प्रभाग क्र. ०६ बरेक नं २४५, २३० मध्ये नाला बनविणे.	१०००००			
	८	प्रभाग क्र. ६ साई ज्योत अपार्टमेंट मध्ये सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	९	उल्हासनगर ३ मधील सती अपार्टमेंट जवळ सीसी फुटपाथ नाला बनविणे	१०००००			
	१०	प्रभाग क्र. ७ मधील हानुमान नगर मध्ये कल्वट बसविणे.	१०००००			
	११	प्रभाग क्र. ६ मधील चॉपणी नाकेंट सनसार दुपडा जवळ सीसी फुटपाथ बनविणे	१०००००			
	१२	नवीन डिंगवानीनी हाऊस बरेक नं २४५, २५१ येथे सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	१३	उल्हासनगर ३ मधील समशान भूमी मध्ये लाल माती टाकणे व झाडे लावणे.	१०००००			
	१४	उल्हासनगर १ मधील समशान भूमी मध्ये लाल माती टाकणे व झाडे लावणे.	१०००००			
	१५	प्रभाग क्र. ६ मधील बरेक नं २२४ मध्ये सीसी फुटपाथ नाला बनविणे.	१०००००			
	१६	उल्हासनगर ३ मधील रामधर्मी गुप्ता हाऊस ते धिरेदु वमा हाऊस आणि सिमा यादव हाऊस ते मंगेश हाऊस सेव्युटी गार्डन जवळ सीसी रोड नाला बनविणे.	१०००००			
	१७	प्रभाग क्र. ६ मधील भाजी मार्केट जवळ सीसी रोड नाला बनविणे	१०००००			
	१८	उल्हासनगर ३ मध्ये विविध टिकाणी बँचेस बसविणे.	१०००००			
	१९	प्रभाग क्र.६ मधील बरेक नं २३३, २०३ मध्ये सीसी रोड नाला बनविणे.	१०००००			
	२०	उल्हासनगर महानगरपालिका च्या मागे सीसी रोड नाला बनविणे.	१०००००			
	२१	उल्हासनगर ३ मधील सनगा गाडन मध्ये लाल माती टाकणे व झाडे लावणे.	१०००००			
	२२	उल्हासनगर १ मधील गोल मैदान मध्ये लाल माती टाकणे व झाडे लावणे	१०००००			
	२३	टाउन हॉल जवळील पणू गार्डन विकसित करणे.	१०००००			
	२४	प्रभाग क्र. ५ मधील बरेक नं ४८५ मध्ये ड्रेन व सीसी पैसेज बनविणे	१०००००			
	२५	प्रभाग क्र. ५ मधील बरेक नं ४८७ च्या मागे बनविणे.	१०००००			
	२६	प्रभाग क्र. ५ मध्ये पीसीआय न्यूज च्या समोर चेवरेक काम करणे	१०००००			
	२७	प्रभाग क्र. ५ मधील बरेक नं ४८६ मध्ये चेवर बनविणे.	१०००००			
	२८	प्रभाग क्र. ५ मधील बरेक नं ४८७ मध्ये नाली रिपेरींग करणे.	१०००००			
	२९	प्रभाग क्र. ५ मधील जवशंकर आश्रमच्या समोर चेवर रिपेरींग करणे.	१०००००			
	३०	प्रभाग क्र. ५ मधील जवशंकर आश्रमच्या समोर चेवर व सीसी रिपेरींग करणे.	१०००००			
	३१	प्रभाग क्र. ५ मधील चेवर व सीसी पैसेज करणे.	१०००००			
	३२	प्रभाग क्र. ५ मधील शितला मंदिर च्या समोरील रोडवर लिफ्ट चेवर आणि टॉयलेट बनविणे.	१०००००			
	३३	प्रभाग क्र. ५ मधील बरेक नं ४९१ मध्ये चेवर आणि सीसी पैसेज बनविणे.	१०००००			
	३४	प्रभाग क्र. ५ मधील ओम शांती धर्मशाळे समोर बरेक नं ४९२ मध्ये ३ मोटे	१०००००			
	३५	चेवर आणि सीसी पैसेज बनविणे.	१०००००			
	३६	प्रभाग क्र. ५ मधील सदागुरु टॉवर जवळील नाली रिपेरींग करणे.	१०००००			
	३७	उल्हासनगर महानगरपालिका जवळ सीसी पेवमेंट ड्रेन बनविणे.	१०००००			
	३८	सपना गाडन क्लिडून्स पार्क जवळ सीसी पेवमेंट ड्रेन बनविणे.	१०००००			
	३९	पणू गाडन टाउन हॉल जवळ सीसी पेवमेंट ड्रेन बनविणे.	१०००००			
	४०	पिलद्वस पार्क सपना गाडनचे विकसित करणे.	१०००००			
	४१	महानगरपालिका प्रयोगशाळेजवळ नाली बनविणे.	१०००००			
	४२	सी ब्रॉक गुरुद्वारा जवळील गाडनचे विकसित करणे.	१०००००			
	४३	प्रभाग क्र. ७ मधील दुर्गा नगर येथे नाला बनविणे.	१०००००			
	४४	शांतीनगर समशान भूमीचे सुरोभिकरण करणे आणि गवत लावणे.	१०००००			
	४५	नुने टेलिफोन ऑफिस जवळ सीसी पेवमेंट आणि ड्रेन बनविणे.	१०००००			
	४६	प्रभाग क्र. ४ मधील लावू तबेला जवळ सीसी पेवमेंट आणि ड्रेन बनविणे.	१०००००			
	४७	प्रभाग क्र.५ मधील साई बाबा मंदीर जवळील गाडन विकसित करणे.	१०००००			
	४८	प्रभाग क्र. १२ मधील आशिर्वाद सोसायटी बरेक नं १००० परिसरत सीसी नाली करणे.	१०००००			
			४८०००००/-			

सदर निविदा प्रणालीबाबत इतर आवश्यक माहिती <https://mahatenders.gov.in/> या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

जा क्र: उमपा/ पीआरओ /०१/२०२५
दिनांक ०१/०४/२०२५

सही/-

कार्यकारी अभियंता (साबावि)
उल्हासनगर महानगरपालिका

मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस

मेमन परिवार को संपत्तियां खाली करने का आदेश

32 साल बाद टाडा कोर्ट का फैसला

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में एक विशेष टाडा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने टाइगर मेमन, याकूब मेमन और उनके परिवार की 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। इनमें कई फ्लैट, खाली प्लॉट, ऑफिस और दुकानें शामिल हैं। इन संपत्तियों को 1994 में अटैच किया गया था। फिलहाल ये संपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के कोर्ट रिसीवर के पास हैं। विशेष न्यायाधीश वी.डी. केदार ने 26 मार्च को यह आदेश दिया, जिसकी प्रति मंगलवार को प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि कोर्ट रिसीवर को इन 14 संपत्तियों से मुक्त किया जाता है। संपत्तियों को बेचने या किसी अन्य कानूनी तरीके से निपटाने के बाद जो भी खर्चा होगा, उसे सक्षम प्राधिकारी को देना होगा।



परिवार को प्रॉपर्टी खाली करने का आदेश

संपत्तियों को खाली करने के नोटिस मेमन परिवार के 13 सदस्यों को भेजे गए थे, जिनमें टाइगर मेमन भी शामिल था। लेकिन किसी ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज

मैन्युपुलेटर्स एक्ट (SAFEMA) के तहत 7 जनवरी, 2025 को यह याचिका दायर की थी। सरकार का कहना है कि इस अर्थोपरीति का काम स्मगलर्स और ड्रग तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाना और

टाइगर मेमन की कितनी प्रॉपर्टी ?

टाइगर मेमन बम धमाकों का मुख्य आरोपी है और वह अभी भी फरार है। उसके भाई याकूब मेमन को इस मामले में दोषी पाया गया था और उसे 2015 में फांसी दी गई थी। जिन संपत्तियों को सरकार को सौंपा जाएगा, उनमें बांद्रा (पश्चिम) के अलमेडा पार्क में याकूब का प्लॉट, सांताक्रूज में एक खाली प्लॉट और प्लैट, कुर्ली में दो प्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक ऑफिस, डोंगरी में एक दुकान, प्लैट और जमीन, माहिम में एक खुला प्लॉट, मनीष मार्केट में तीन दुकानें, जावेरी बाजार में एक इमारत और प्लॉट, और माहिम में एक गैरेज शामिल है। इन संपत्तियों के मालिक अब्दुल रज्जाक मेमन, इरसा मेमन, याकूब मेमन और रुबीना मेमन हैं।

उन्हें जब्त करना है। SAFEMA एक कानून है जो सरकार को स्मगलिंग और विदेशी मुद्रा के हेरफेर से कमाए गए पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।

सैफ अली खान हमला केस कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब



मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला मामले में आरोपी शरीफुल की जमानत याचिका पर एक अप्रैल को सुनवाई होनी थी लेकिन अब इसे 4 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई। दरअसल, पुलिस ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था, जिसकी वजह से कार्यवाही में देरी हुई। अगली सुनवाई अब 4 अप्रैल को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने पुलिस को

बेल एप्लीकेशन के संबंध में अपना जवाब सबमिट करने का निर्देश दिया है। अपनी याचिका में शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद ने खुद को निर्दोष बताया है और दावा किया है कि उसके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। अपने वकील अजय गवली के माध्यम से दिए आवेदन में तर्क दिया गया है कि एफआईआर अनुचित तरीके से दर्ज की गई थी।

पुलिस ने अब तक फाइल नहीं की चार्जशीट

शहजाद ने यह भी कहा कि उसने जांच में पूरा सहयोग किया है और सभी आवश्यक सबूत पहले से ही पुलिस के पास हैं। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ मुश्किल है। फिलहाल यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है और पुलिस के चार्जशीट दाखिल करने के बाद इसे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाने की उम्मीद है। अभी तक बांद्रा पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं की है। वहीं, सैफ पर जानलेवा हमले मामले में पकड़े गए संदिग्ध आकाश कर्नौजिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार

लगाई है। उसका दावा है कि पकड़े जाने की खबर मीडिया में प्रसारित होने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। यहां तक कि उसकी शादी भी टूट गई। अब रिश्तेदारों ने भी उससे दूरी बना ली है। नौकरी के लिए दर-दर भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा है। सामाजिक और आर्थिक नुकसान होने के बाद अब उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके आत्महत्या कर लेने के विचार आने की जानकारी लगने के बाद एक समाजसेवी ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई है।

ऐसे जल्ट हुई थी टाइगर मेमन की प्रॉपर्टी

सरकार ने बताया कि टाइगर मेमन के खिलाफ 1992 में महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के तहत एक डिटेन्शन ऑर्डर जारी किया था। COFEPOSA एक कानून है जो सरकार को स्मगलिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है। इसके बाद, 1993 में SAFEMA के तहत अधिकारियों ने उसकी कई संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। लेकिन 1994 में टाडा अदालत ने इन संपत्तियों को अटैच कर दिया और एक कोर्ट रिसीवर को उनकी कस्टडी दे दी। टाडा एक ऐसा कानून था जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से जुड़े मामलों में किया जाता था।

प्रॉपर्टी रिलीज के लिए हुई थीं याचिकाएं

पिछले कुछ सालों में जिन लोगों की संपत्तियां जब्त की गईं, उन्होंने उन्हें वापस पाने के लिए कई अदालतों में याचिकाएं दायर कीं। लेकिन उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अगस्त 2024 में अदालत ने माहिम की अल हुसैन बिल्डिंग में स्थित तीन प्लेटों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया था। ये प्लैट कभी मेमन परिवार के थे। इन प्लेटों का संबंध टाइगर, याकूब और उनके रिश्तेदारों से

था, जिनमें उनकी मां हनीफा (जिन्हें बरी कर दिया गया था), भाभी रुबीना (जो आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं), और पत्नी शबाना (जो फरार हैं) शामिल हैं। हाउसिंग सोसाइटी ने प्लेटों के रखरखाव के बकाया और पुनर्विकास के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया और उन्हें सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया।

बुच के खिलाफ प्राथमिकी के आदेश पर रोक बढ़ी

मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ FIR आदेश पर रोक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने भी इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। जस्टिस शिवकुमार डिगे ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मामले में हलफनामा दाखिल किया है और बुच और अन्य आरोपियों को इसकी जांच करने के लिए समय दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 7 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मार्च में बुच समेत SEBI के पांच शीर्ष अधिकारियों ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।



1 मार्च को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने दिया था FIR का आदेश

1 मार्च को मुंबई की एक स्पेशल एंटी-कॉर्रप्शन कोर्ट ने माधवी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

प्रशांत कोरटकर की जमानत याचिका खारिज

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक बयान देने और इतिहासकार इंदुजित सावंत को धमकी देने के मामले में प्रशांत कोरटकर की जमानत याचिका मंगलवार को कोल्हापुर जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। अब, कोरटकर के वकील को कोल्हापुर सेशन कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल करनी होगी। रविवार को कोल्हापुर जिला कोर्ट ने कोरटकर को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद कोरटकर के वकील ने जमानत याचिका को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोरटकर के फरार होने की आशंका जताई, जबकि कोरटकर के वकील ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और फरार नहीं होंगे। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोरटकर, जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान देने के बाद फरार हो गए थे, को करीब एक माह बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सुरक्षा कारणों से कलंबा जेल की अंडा सेल में रखा गया है।



मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल

(महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण की एक क्षेत्रीय इकाई)

निविदा सूचना संख्या ईई/पूर्व/एमएसआईबी/ई-टेंडर/यूई/10/2024-25

कार्यकारी अभियंता (पूर्व) प्रभाग, मुंबई झोपड़पट्टी सुधार बोर्ड, (महाडा की इकाई) कमरा संख्या 536, चौथी मंजिल, गृह निर्माण भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 फोन नंबर (022) 66405251 मुंबई उपनगरीय जिले में उपयुक्त वर्ग में महाडा/पीडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत बेरोजगार इंजीनियरों से बीआई (प्रतिशत दर) के रूप में 02 कार्यों के लिए ई-टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। विस्तृत निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज उपलब्ध होंगे और महाराष्ट्र सरकार के पोर्टल <https://mahatenders.gov.in> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोली दस्तावेज वेबसाइट पर लोड किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज की बिक्री दिनांक 04/04/2025, सुबह 10.05 बजे से शुरू होकर दस्तावेज बिक्री की अंतिम तिथि 11/04/2025, शाम 6.15 बजे तक होगी। शुद्धिपत्र/संशोधन यदि कोई हो तो केवल <https://mahatenders.gov.in> वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Follow us: @mhadaofficial

सीपीआरओ/ए/234

महाडा-राष्ट्र में अग्रणी आवास प्राधिकरण

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

मुख्य अभियंता (आरडीएस और टीआर)

ई-निविदा सूचना

निविदा दस्तावेज संख्या	2025_MCGM_1166656
संगठन का नाम	बृहन्मुंबई महानगर पालिका
विषय	वर्ली के डामर प्लॉट में बैच मिक्स प्लॉट के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (P.L.C.) के साथ ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (S.I.T.C.) के लिए निविदा आमंत्रित करना।
ई-निविदा की लागत (अनुमानित लागत)	₹.21,16,450.00 (जीएसटी को छोड़कर)
निविदा जांच शुल्क	₹. 3630+18% यानी ₹.4285/-
ईएमडी	₹.24,975/-
निविदा जारी करने और बेचने की तिथि	02/04/2025 11:00 बजे से
निविदा बेचने की अंतिम तिथि और समय	10/04/2025 16:00 बजे तक
पैकेट ए और बी जमा करना (ऑनलाइन)	10/04/2025 16:00 बजे तक
पूर्व-बोली बैठक	एनए
पैकेट ए खोलना	11/04/2025 16.15 बजे के बाद
पैकेट बी खोलना	11/04/2025 16.20 बजे के बाद
वेबसाइट	http://mahatender.gov.in
संपर्क व्यक्ति	श्री शगुन पवार (ईई):-8879646460 श्री. विश्वास धेंडे (एसई):- 9920978240 श्री. विशाल लोटेकर (जेई): 7058555100
संपर्क के लिए पता	सहायक अभियंता डामर प्लॉट, एस.के. अहिरे मार्ग, मेफेयर होटल के सामने, वर्ली, मुंबई-400 025
बोली खोलने का स्थान	सहायक अभियंता डामर प्लॉट, एस.के. अहिरे मार्ग, मेफेयर होटल के सामने, वर्ली, मुंबई-400 030 के कार्यालय में ऑनलाइन।

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

बीएमसी बिना कोई कारण बताए उपरोक्त विषय के लिए प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार करने या किसी या सभी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

हस्ता./-

सहायक अभियंता (डामर प्लॉट)

पीआरओ/09/विज्ञा./2025-26

समय पर उपचार, बचाएं प्राण।

सीएम फडणवीस ने महाबलेश्वर पर्यटन महोत्सव के बोध चिन्ह का किया लोकार्पण



मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को मुंबई में महाबलेश्वर पर्यटन महोत्सव के बोध चिन्ह का लोकार्पण किया। यह महोत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से 7-9 मई 2025 तक सातारा जिले के महाबलेश्वर में आयोजित किया जाएगा।

महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन 2 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जिसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई और पर्यटन राज्य मंत्री इंदुनील नाइक भी शामिल होंगे।

महोत्सव का उद्देश्य

यह महोत्सव पर्यटकों को स्थानीय कला, संस्कृति, और खाद्य संस्कृति से परिचित कराते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। तीन दिवसीय महोत्सव में लोक संस्कृति के साथ-साथ प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, पर्यटन मंत्री शंभूराजे देसाई, राज्य मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव सुजाता सोनिक, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव अतुल पाटने, एमटीडीसी के प्रबंध निदेशक मनोज सूर्यवंशी, पर्यटन निदेशक डॉ. वीरन पाटिल, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा में 75 की उम्र में रिटायरमेंट का नियम नहीं : बावनकुले

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को 75 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा। यह देश की जनता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का फैसला करेगी, न कि संजय राउत। उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के दौरे को रिटायरमेंट प्लान बताया था। बावनकुले ने राउत के इस बयान को राजनीतिक स्टेट बताया था।



'भारतीय संविधान भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से संजय राउत के दावे को खारिज किए जाने के एक दिन बाद बावनकुले ने 'एक्स' पर कहा, 'भाजपा में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे पीएम मोदी को 75 साल की

उम्र के बाद राजनीति से रिटायर होना पड़ेगा। ऐसा कोई फैसला कभी भी नहीं हुआ है।' बावनकुले ने आगे कहा कि भारतीय संविधान भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं करता है।

'भाजपा के प्रति अपनी दुश्मनी में अंधे राउत'

उन्होंने कहा, 'पूर्व भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी 79 वर्ष की आयु तक प्रधानमंत्री रहे, जबकि मोरारजी देसाई (83) और डॉ. मनमोहन सिंह (81) भी 75 वर्ष की आयु के बाद भी प्रधानमंत्री रहे। हालांकि, भाजपा के प्रति अपनी दुश्मनी में अंधे राउत यह भूल गए हैं।'

'प्रधानमंत्री का कार्यकाल चुनावी जनादेश और जनता के समर्थन से तय होता है'

बावनकुले ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का कार्यकाल चुनावी जनादेश और जनता के समर्थन से तय होता है, न कि राउत जैसे व्यक्तियों से। उन्होंने कहा, 'इस देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल का फैसला करती है, न कि संजय राउत या विपक्ष।'

'मोदी 2029 के बाद भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे'

भाजपा नेता ने कहा कि मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और यह सपना

उन्हें नेतृत्व में साकार होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में

अपने तीसरे कार्यकाल में हैं और इस साल सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे। 2029 के बाद भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे।

देश की सभी ग्राम पंचायतों को तीव्र संचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा: सिंधिया

डीबीडी संवाददाता | मुंबई
केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को मुंबई में एक बैठक के दौरान बताया कि भारत सरकार जल्द ही देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को तीव्र संचार प्रणाली से जोड़ेगी। इसके लिए भारत नेट परियोजना को लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सुदूरतम क्षेत्रों में भी अच्छी संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना है।



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार गढ़चिरोली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था की स्थापना में केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि गढ़चिरोली में सुरक्षा की उचित व्यवस्था के साथ टावर निर्माण किया जाएगा, जिससे यहां के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सकेगा।

राज्य सरकार ने दिया सहयोग का आश्वासन

मुख्य बैठक में अन्य लोग
इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, केन्द्रीय दूरसंचार सचिव नीरज कुमार, और बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट रवि भी उपस्थित थे।

भारत नेट फेज-2 के तहत 1 लाख 4जी नेटवर्क टावरों का निर्माण

सिंधिया ने कहा कि भारत नेट फेज-2 के तहत देशभर में 1 लाख 4जी नेटवर्क टावर लगाए जाएंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य असंबद्ध क्षेत्रों में संचार सेवाओं का विस्तार करना है। इस पहल से ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और संचार सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।

अधिकारियों को निर्देश
सिंधिया ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की कंपनियों को लेकर एक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो शहरी विकास विभाग, बीएसएल और केन्द्रीय दूरसंचार विभाग के अधिकारियों से मिलकर चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

पश्चिम रेलवे ने बंद किए 105 लेवल क्रॉसिंग

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में मुंबई सेंट्रल मंडल ने पिछले पांच वर्षों में 105 लेवल क्रॉसिंग बंद करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इनमें इंटरलॉक और नॉन-इंटरलॉक दोनों प्रकार की क्रॉसिंग शामिल हैं। रेलवे पर लेवल क्रॉसिंग बंद करने से कई फायदे मिलते हैं, जिनमें संरक्षा बढ़ाना, सड़क और रेल यातायात में सुधार, कंजेशन कम करना, दुर्घटनाओं में कमी और ट्रेनों की गति बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे समग्र रेल परिचालन अधिक सुचारू और कुशल बनता है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि लेवल क्रॉसिंग बंद होने से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार हुआ है, जिससे दुर्घटनाओं और जान-माल की हानि की संभावना कम हो गई है। उन्होंने कहा कि संरक्षा उपायों से यात्रियों और समुदायों पर पड़ने वाले भावनात्मक व आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद मिली है।

यातायात और कंजेशन में कमी



अब बिना रुकावट के अधिकतम 160 किमी/घंटे की गति से चलाने में सुविधा होगी।

मुंबई-वडोदरा-दिल्ली सेक्शन जैसे व्यस्त मार्गों पर लेवल क्रॉसिंग को बंद करने से ट्रैफिक कंजेशन में कमी आई है। इन मार्गों पर वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें चलती हैं, जिन्हें अब बिना रुकावट के अधिकतम 160 किमी/घंटे की गति से चलाने में सुविधा होगी।

आर्थिक और रेलवे परिचालन में लाभ
लेवल क्रॉसिंग बंद करने से रेलवे को संरक्षा और दक्षता बढ़ाने में मदद मिली है। इससे रेलगाड़ियों के संचालन में देरी कम हुई है, जिससे यात्रा का समय घटा है और रेलवे का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। साथ ही, लेवल क्रॉसिंग के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी बचाया गया है।

यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं पर रहेगा जोर
विनीत अभिषेक ने कहा कि पश्चिम रेलवे यात्रियों के सफर को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार और बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर निरंतर कार्य करता रहेगा।

केडीएमसी के 2068 सफाई कर्मचारियों को मिलेगा आश्वासित योजना का लाभ

सुशील सिंह | कल्याण

कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) प्रशासन ने 10 से 30 वर्षों तक सेवा देने वाले 2068 सफाई कर्मचारियों को आश्वासित प्रगति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना के निरंतर प्रयासों के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे सफाई कर्मचारियों को वर्षों बाद न्याय मिला है।

पदोन्नति न मिलने वाले कर्मचारियों को मिला हक



पिछले वर्ष निगम के लिपिक संवर्ग के 1500 से अधिक कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया गया था। कई वर्षों की सेवा के बावजूद, तकनीकी कारणों या पदों की कमी के चलते पदोन्नति से वंचित रहे कर्मचारियों को यह योजना राहत प्रदान करती है।

संघ के प्रयासों से मिली सफलता

म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना के अध्यक्ष बंदा हरदास, कार्योध्यक्ष अजय पवार, उपाध्यक्ष सुरेश तेलवणे, सुनील पवार, और सरचिटणीस सचिन बासरे के नेतृत्व में पिछले 2-3 वर्षों से प्रशासन से इस योजना के क्रियान्वयन की मांग की जा रही थी।

सातवें वेतन आयोग के तहत मिली राहत

सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार, 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा करने वाले कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति या उसके लाभ नहीं मिलने से उनकी कुंठा दूर करने के लिए इस योजना का लाभ आवश्यक है।

अन्य लंबित मामलों पर भी हो रहा कार्य

संघ के सरचिटणीस सचिन बासरे ने बताया कि प्रशासन द्वारा जल्द ही इन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे वेतन, सेवानिवृत्ति वेतन और परिवार सेवानिवृत्ति वेतन में सुधार होगा। साथ ही, अन्य संवर्गों के 3636 लंबित मामलों को भी हल करने के प्रयास जारी हैं।

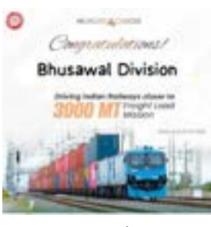
लोको पायलट सुरजीत सिंह हुए सेवा निवृत्त

लोको पायलट सुरजीत सिंह ने 32 साल की सेवा के बाद 31 मार्च 2025 को सेवा निवृत्ति ली। उनकी गौरवशाली सेवा का समापन एक महत्वपूर्ण क्षण है, और इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 2 अप्रैल 2025 को शाम 6:00 बजे कल्याण रेलवे इंस्टीट्यूट में एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुरजीत सिंह की सेवा को सम्मानित किया जाएगा और उनके समग्र और कार्यक्षमता की सराहना की जाएगी।

मिशन 3000 मीट्रिक टन योजना में भुसावल मंडल का अहम योगदान

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय रेलवे की मालवाहन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई मिशन 3000 मीट्रिक टन योजना के तहत, भुसावल मंडल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भुसावल C&W विभाग ने मालगाड़ियों के रखरखाव में 34.7% वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2025 में 702 वैगनों का सफलतापूर्वक आरओएच (ROH) किया गया, जो मार्च 2024 में 441 वैगनों के मुकाबले 59.1% अधिक था। भुसावल मंडल में CC मालगाड़ी रोक की संख्या में भी 1,689 CC मालगाड़ी रोक परीक्षण पूरे किए गए, जो 2023-24 के 1,271 परीक्षणों से 32.88% अधिक है। इस सफलता से मालवाहन की सुरक्षा और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि मंडल रेल प्रबंधक इति पांडे और प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता सुबोध कुमार सागर के कुशल नेतृत्व में प्राप्त की गई है। इसके अलावा, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता रोहित राजपूत और सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता अमित वाघ के मार्गदर्शन और सक्रिय भागीदारी से यह सफलता संभव हुई है।



महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मार्च 2025 में 238 CC मालगाड़ी रोक की संख्या रही, जो मार्च 2024 के 133 रोक से 78.94% अधिक है। यह वृद्धि मालवाहन क्षमता को बढ़ाने में सहायक रही है। वर्ष 2024-25 में

भुसावल मंडल ने अर्जित किया 1625.46 करोड़ का राजस्व

डीबीडी संवाददाता | भुसावल

भुसावल मंडल, जो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ रेल राजस्व में भी योगदान दे रहा है, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक नई उपलब्धि हासिल की है। मंडल ने 1625.46

करोड़ का कुल रेल राजस्व अर्जित किया, जिसमें माल ढुलाई, यात्री परिवहन सेवा और अन्य कोचिंग आय शामिल हैं। मंडल ने विभिन्न श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे यह वित्तीय वर्ष रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है।

विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन

वाणिज्यिक प्रचार राजस्व: भुसावल मंडल ने 7.58 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष 6.49 करोड़ से अधिक है। यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टिकट जांच प्रदर्शन: टिकट जांच अभियानों के तहत, मंडल ने 56 करोड़ वसूल किए, जो बेहतर टिकटिंग व्यवस्था और यात्रियों के लिए नए डिजिटल उपायों का परिणाम है।

टिकट बिक्री में 93.34% वृद्धि की। माल ढुलाई राजस्व: भुसावल मंडल ने 645.76 करोड़ का मालभाड़ा राजस्व अर्जित किया, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

पार्सल आय: मंडल ने 29.96 करोड़ का पार्सल आय अर्जित किया, जो पिछले वर्ष से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। इस सफलता के पीछे शेतकरी समुद्धि विशेष रेल और UTS-QR कोड डिस्के जैसी पहलें प्रमुख रही हैं।

खानपान राजस्व: मंडल ने 10.92 करोड़ का खानपान राजस्व अर्जित किया, जो लक्षित राशि से अधिक है।

कोशिंग उपलब्धियां: भुसावल मंडल ने 100% डिजिटल टिकटिंग और यूटीएस

यात्री राजस्व: मंडल ने 858.00 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के 844.33 करोड़ से अधिक है।

अन्य राजस्व: अन्य राजस्व में 12.34% की वृद्धि हुई और कुल 27.80 करोड़ अर्जित किया गया।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी चार समर स्पेशल ट्रेनें

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा था विशेष रूप से ग्रीष्मकाल के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर चार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने इसकी जानकारी दी।



बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झॉसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 02200 बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झॉसी स्पेशल प्रत्येक शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 05.10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05.00 बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झॉसी पहुंचेगी। यह ट्रेन 05 अप्रैल से 28 जून, 2025 तक चलेगी। इसी

तरह, ट्रेन संख्या 02199 वीरांगना लक्ष्मीबाई झॉसी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई झॉसी से 16:50 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 अप्रैल से 26 जून, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरुक, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मवसी, बियावार राजगढ़, चयुरा बीनागंज, रुटियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, उबरा और दतिया स्टेशनों पर रुकेगी।

बांद्रा टर्मिनस - सुबेदारगंज सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 04126 बांद्रा टर्मिनस-सुबेदारगंज सुपरफास्ट स्पेशल हर मंगलवार को बांद्रा टर्मिनस से 11:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17:00 बजे सुबेदारगंज पहुंचेगी। यह ट्रेन 08 अप्रैल से 01 जुलाई, 2025 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 04125 सुबेदारगंज-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल हर सोमवार को सुबेदारगंज से 05:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 09:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 07 अप्रैल से 30 जून 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापूर सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी और फतेहपुर स्टेशनों पर रुकेगी।

असारवा - कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल (26 फेरे)

ट्रेन संख्या 01906 असारवा-कानपुर ट्रेन 7 अप्रैल से 30 जून, 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में हिममत नगर, झुंगरपुर, जावर, उदयपुर सिटी, मावली जं., चंदेरिया, मंडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापूर सिटी, बयाना, फतेहपुर सीकरी, ईदगाह, टूंडला, फिरोजाबाद और इटावा स्टेशनों पर रुकेगी।

दिन 05.45 बजे असारवा पहुंचेगी। ट्रेन 7 अप्रैल से 30 जून, 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में हिममत नगर, झुंगरपुर, जावर, उदयपुर सिटी, मावली जं., चंदेरिया, मंडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापूर सिटी, बयाना और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रुकेगी।

असारवा-आगरा कैंट स्पेशल (प्रतिदिन) [182 फेरे]

ट्रेन संख्या 01920 असारवा-आगरा कैंट स्पेशल प्रतिदिन असारवा से 18.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.20 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 अप्रैल से 1 जुलाई, 2025 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 01919 आगरा कैंट-असारवा स्पेशल प्रतिदिन आगरा कैंट से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.35 बजे असारवा पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 अप्रैल से 30 जून, 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में हिममत नगर, झुंगरपुर, जावर, उदयपुर सिटी, मावली जं., चंदेरिया, मंडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापूर सिटी, बयाना और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रुकेगी।

असारवा-आगरा कैंट स्पेशल (प्रतिदिन) [182 फेरे]
ट्रेन संख्या 01920 असारवा-आगरा कैंट स्पेशल प्रतिदिन असारवा से 18.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10.20 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 अप्रैल से 1 जुलाई, 2025 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 01919 आगरा कैंट-असारवा स्पेशल प्रतिदिन आगरा कैंट से 23.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.35 बजे असारवा पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 अप्रैल से 30 जून, 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में हिममत नगर, झुंगरपुर, जावर, उदयपुर सिटी, मावली जं., चंदेरिया, मंडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापूर सिटी, बयाना और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रुकेगी।

श्री राम नवमी पर निकलेगी शोभा यात्रा

डीबीडी संवाददाता | कल्याण

भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली श्री राम नवमी के अवसर पर, विराट हिंदू शक्ति द्वाय 6 अप्रैल 2025 को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करने का संदेश लेकर निकलेगी। इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम के विचारों और शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। आयोजकों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से लोग श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं।



यात्रा का मार्ग और प्रमुख पड़ाव

शोभा यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू होकर विठ्ठल मंदिर, हनुमान नगर, कटेमनिवाली ब्रिज, उत्तेकर चौक और दुर्गा माता मंदिर कोलसेवाडी तक निकलेगी। यह शोभा यात्रा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज में भाईचारे और एकता का संदेश भी देगी। आयोजक इस अवसर पर सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का भी प्रयास करेंगे।

प्रियंका जैन राशिफल

नियं यात्रा लंबी तथा मनोरंजक रह सकती है। अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। जीवन सुखमय व्यतीत होगा। प्रसन्नता तथा उत्साह से ओत-प्रोत रहेंगे।

वृष जल्दबाजी से चोट लग सकती है। कुसंगति से बचें। कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आएगा। कर्ज लेना पड़ सकता है। असमंजस की स्थिति बनेगी। लेन-देन में जल्दबाजी व लापरवाही न करें। भावनाओं को वश में रखें।

मिथुन प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकते हैं। बेवजह तनाव रह सकता है। सिर में चोट लग सकती है। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में अतिथियों का आगमन होगा। व्यय बढ़ेगा।

कन्या ऐश्वर्यादि पर खर्च होगा। यश बढ़ेगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नए काम मिल सकते हैं। आर्थिक वृद्धि के लिए योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। नौकरी में जवाबदारी बढ़ सकती है।

तुला बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम आ सकता है। सुजनशीलता का विकास होगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। व्यापार-व्यवसाय सुखद रहेगा। जल्दबाजी न करें। शारीरिक कष्ट संभव है।

वृश्चिक शत्रु पीठ पीछे षडयंत्र रच सकते हैं। प्रियजनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। दूर से दुःखद समाचार मिल सकता है। पुराने रोग को नजरअंदाज न करें। व्यय होगा।

मकर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी चिंता रहेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा।

कुम्भ सुख के साधन जुटेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। मित्रों का साथ मिलेगा। प्रयास सफल रहेंगे। किसी विवाद में विजय मिल सकती है। सामाजिक काम करने का मन बनेगा।

मीन बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। मित्रों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

वहिन वहिन व मशीनों के प्रयोग में लापरवाही न करें। अनहोनी की आशंका निर्मूलत नहीं हो सकती है। पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दूसरों के मामलों में हाथ न डालें। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी व्यक्ति के व्यवहार से क्लेश होगा।

कर्क किसी भी व्यक्ति के उरुसाने में न आएं। बातचीत में संयम रखें। शत्रुता में कमी रहेगी। स्थायी संपत्ति की खरीदी-बिक्री की योजना बनेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। पार्टनरों तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

वृश्चिक शत्रु पीठ पीछे षडयंत्र रच सकते हैं। प्रियजनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। दूर से दुःखद समाचार मिल सकता है। पुराने रोग को नजरअंदाज न करें। व्यय होगा।

मीन बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। मित्रों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

शनि और चन्द्रमा जन्त विषयो ग विवरण

भाग-2
‘बृहज्जातक’ तथा ‘फलदीपिका’ ने इसका फल ‘परपुरुष से उदयन, आदि’ बताया है। अशुभ फलदेश के कारण इस युति को ‘विष योग’ की संज्ञा दी गई है। ‘विष योग’ का अशुभ फल जातक को चंद्रमा और शनि की दशा में उनके बलानुसार अधिक मिलता है। कटक शनि, अष्टम शनि तथा साडेसाती कष्ट बढ़ाती है। कुंडली में जिस भाव में ‘विष योग’ स्थित होता है उस भाव संबंधी कष्ट मिलते हैं। नजदीकी परिवारजन स्वयं दुखी रहकर विश्वासघात करते हैं। जातक को दीर्घकालीन रोग होते हैं और वह आर्थिक तंगी के कारण कर्ज से दबा रहता है। जीवन में सुख नहीं मिलता। जातक के मन में संसार से विरक्ति का भाव जागृत होता है और वह अध्यात्म की ओर अप्रसर होता है।

भावानुसार ‘विष योग’ का फल
प्रथम भाव (लग्न) - इस योग के कारण माता के बीमार रहने या उसकी मृत्यु से किसी अन्य स्त्री (बुआ अथवा मौसी) द्वारा उसका बचपन में पालन-पोषण होता है। उसे सिर

कमाता है। भाई-बहनों के साथ संबंध में कटुता आती है। नौकर विश्वासघात करते हैं। यात्रा में विघ्न आते हैं। श्वास के रोग होने की संभावना रहती है।

चतुर्थ भाव - माता के सुख में कमी, अथवा माता से विवाद रहता है। जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। मध्यम आयु में आय कुछ ठीक रहती है, परंतु अंतिम समय में फिर से धन की कमी हो जाती है। स्वयं दुखी दरिद्र होकर दीर्घ आयु पाता है। उसके मृत्योपर्यंत ही उसकी संतान का भाग्योदय होता है। पुरुषों को हृदय रोग तथा महिलाओं को स्तन रोग की संभावना रहती है।

पंचम भाव - में विष योग होने से शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है। वैवाहिक सुख अल्प रहता है। संतान देरी से होती है, या संतान मंदबुद्धि होती है। स्त्री राशि में कन्याएं अधिक होती हैं। संतान से कोई सुख नहीं मिलता।

षष्ठ भाव - जातक को दीर्घकालीन रोग होते हैं। ननिहाल पक्ष से सहायता नहीं मिलती। व्यवसाय में प्रतिद्वंद्वी हानि करते हैं। घर में चोरी की संभावना रहती है।

शनि और चन्द्रमा जन्त विषयो ग विवरण
होती। नौकरी में पदोन्नति देरी से होती है। विवाह देर से होता है। दौपत्य जीवन सुखी नहीं रहता। इस प्रकार जीवन में कठिनाइयां भरपूर होती हैं।

द्वितीय भाव - घर के मुखिया की बीमारी या मृत्यु के कारण बचपन आर्थिक कठिनाई में व्यतीत होता है। पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है। जातक की वाणी में कटुता रहती है। वह कंजूस होता है। धन कमाने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जीवन के उत्तरार्द्ध में आर्थिक स्थिति ठीक रहती है। दांत, गला एवं कान में बीमारी की संभावना रहती है।

तृतीय भाव - जातक की शिक्षा अपूर्ण रहती है। वह नौकरी से धन

आसाराम फिर पहुंचा सलाखों के पीछे, जेल में सरेंडर किया



जोधपुर। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से रेप करने का दोषी आसाराम ने जमानत अवधि खत्म होने पर मंगलवार को फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत 31 मार्च को समाप्त हो गई है। आसाराम के वकील ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट दो अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट में 29 से 31 मार्च तक छुट्टी के बाद मंगलवार को आसाराम के वकील निशांत बोडा ने सुनवाई का आग्रह किया था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के वकील दिनेश जैन ने बताया कि आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के आवेदन पर बुधवार को सुनवाई होगी। यदि कोर्ट अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ाती है तो आसाराम को जेल में ही रहना होगा। जब तक दोनों ही मामलों में उसे राहत नहीं मिलती है, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

बरहट में कोयला ढोने वाली दो मालगाड़ी आपस में टकराई, 2 की मौत

बरहट: मंगलवार की अहले सुबह ललमटिया-फरक्का एमजीआर रेल लाइन पर हुए भीषण हादसे में दो मालगाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे तीन रेल इंजन, सात बोगियां और रेल पट्टी



बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में दो लोको पायलट जिंदा जलकर मौत के शिकार हो गए, जबकि एक लोको पायलट और पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बरहट सोनाजोड़ी लूप लाइन में पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, तभी ललमटिया से फरक्का जा रही दूसरी कोयला लदी मालगाड़ी गलती से लूप लाइन में प्रवेश कर गई। तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिला और सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डीजल इंजन में आग लग गई और दोनों लोको पायलट जिंदा जल गए।

सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए निर्देश



रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी अनुराग गुप्ता) को निर्देश दिया है कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैप हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्रवाई न की जाए। इस आदेश के बाद डीजीपी ने रांची एसएसपी को मामले में कोई आगे की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। 30 मार्च 2025 को रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर का रैप हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, और विधि व्यवस्था में बाधा डाली गई। हालांकि, पुलिस और दंडाधिकारियों ने संयम बरतते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा। इस घटना के संबंध में 30 मार्च को चूटिया थाने में कांड संख्या (77/2025) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नहाय-खाय से चैती छठ का आगाज

- ▶ 2 अप्रैल को खरना, उसके बाद शुरू होगा निर्जला उपवास
- ▶ 3-4 अप्रैल को सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होगा



खरना के बाद शुरू होगा निर्जला उपवास

लोक आस्था के महापर्व चैती छठ पूजा की आज मंगलवार से नहाय-खाय के साथ शुरू हो गई। नहाय-खाय में व्रती स्नान कर नए कप धारण करते हैं और चने की दाल, कढ़ी सब्जी, और चवल ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ-सफाई और शुद्धिकरण पर जोर दिया जाता है।

खरना को दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को पुरे समुद्र में बांटा जाता है। तीसरे दिन संघा अर्घ्य दिया जाता है। यह मुख्य दिन होता है। श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान बांस की टोकरी में टेकुआ, फल और गन्ना रखकर विशेष भागवान भास्कर की पूजा की जाती है। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समाप्त किया जाता है।

रुड़की में हेल्थ क्लब की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

- ▶ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 9 गिरफ्तार



गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने रुड़की के कलियार थाना क्षेत्र में हेल्थ क्लब की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में चार महिलाओं और पांच पुरुषों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

हरिद्वार एसएसपी प्रमोद डोबाल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को देह व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय थाना पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि पिरान कलियार क्षेत्र में एक हेल्थ क्लब की आड़ में जितम्फरोशी का बंध चलाना जा रहा है। सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पिरान कलियार थाना पुलिस ने हेल्थ क्लब पर छापा मारा, जहां से चार महिलाओं और पांच पुरुषों को गिरफ्तार किया गया।

'मैं योगी हूँ, हमेशा के लिए राजनीति में नहीं' योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को किया खारिज

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति में स्थायी रूप से नहीं आए हैं और उनका प्राथमिक उद्देश्य जनता की सेवा करना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं दिल से एक योगी हूँ और राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। भाजपा ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे मैं निभा रहा हूँ, लेकिन हमेशा के लिए राजनीति में नहीं हूँ। प्रधानमंत्री पद की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में एक समय सीमा है और वे इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखेंगे। गौरतलब है कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम चर्चा में है।

धर्म और राजनीति के संबंध पर भी दिया बयान

एजेंसी | लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म और राजनीति के संबंध पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म का समावेश गलत नहीं है। यह हमारी गलती है कि हम धर्म को कुछ स्थानों तक सीमित कर देते हैं और राजनीति को कुछ लोगों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल स्वार्थ सिद्ध करना नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना होना चाहिए। धर्म भी तभी सार्थक होता है जब वह परमार्थ के लिए हो। आधुनिक समाज में धर्म के लिए किया जाने वाला शुद्धिकरण आती है, लेकिन जब इसका उद्देश्य परमार्थ होता है, तो यह समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।



मलिन बस्तियों का होगा कायाकल्प

- ▶ 250 से अधिक परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
- ▶ योगी सरकार ने जारी किए 20 करोड़ रुपए

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में शहरी विकास को नई गति मिल रही है। जहां एक ओर शहरों और कस्बों का तेजी से कायाकल्प हो रहा है, वहीं मलिन बस्तियों में भी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित और मलिन बस्ती योजना के तहत लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, रायबरेली और कन्नौज समेत 17 जिलों में 250 से अधिक विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं के तहत सीसी रोड, इंटरनेटिंग रोड, नाली निर्माण और पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

मलिन बस्तियों के जीवन स्तर में होगा सुधार

एजेंसी | लखनऊ

प्रदेश सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने से मलिन बस्तियों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे राज्य की तस्वीर बदल रही है। जल्द ही इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सड़कें, जल निकासी और उत्तम प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका जीवन अधिक सुगम होगा।

विभिन्न जिलों में परियोजनाओं को मिली वित्तीय स्वीकृति

इस योजना के तहत लखनऊ, प्रयागराज, मऊ, बस्ती, जालौन, सिद्धार्थनगर, मुदाबाद, संतकबीर नगर, जौपुर, बुलंदशहर और महाराजगंज की 166 परियोजनाओं के लिए 3.35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़ और कौशांबी जिलों में 95 परियोजनाओं के लिए 17.53 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।



सेंसेक्स में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट

- ▶ 1390 अंक नीचे 76,024 पर बंद, निफ्टी 353 लुढ़का
- ▶ रियल्टी और IT सेक्टर सबसे ज्यादा टूटे

एजेंसी | मुंबई

वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार (1 अप्रैल) को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1390 अंक (करीब 1.80%) गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ। यह इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले सेंसेक्स में 28 फरवरी को 1414 (1.90%) अंक की गिरावट रही थी। निफ्टी में भी करीब 353 अंक (करीब 1.50%) की गिरावट रही, ये 23,165 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट रही। HCL टेक, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और इंफोसिस में सबसे ज्यादा करीब 4% गिरकर बंद हुए। NSE के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट रही। सेक्टरल इंडेक्स में सबसे तेज गिरावट 3.11%, कंप्यूटर इंडेक्स में 2.50%, IT में 2.45%, फार्मा में 1.73% और प्राइवेट बैंक में 1.21% की गिरावट रही।

एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। यह घोषणा उन एनजीओ पर लागू होगी जिनके नवीनीकरण आवेदन लंबित हैं। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जनहित में एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) की वैधता 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है जिनका लाइसेंस या तो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच समाप्त हो रहा है, या उनका नवीनीकरण आवेदन लंबित है।

206.6 करोड़ रुपए के घटिया आयातित सामानों पर कार्रवाई

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने भारतीय बाजार में घटिया गुणवत्ता के आयातित उत्पादों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने वित्त वर्ष 2024-25 (फरवरी तक) में कुल 206.62 करोड़ रुपए के घटिया माल के आयात पर 206 मामले दर्ज किए हैं।

घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा



कार्रवाई करता है। जांच के बाद डीजीटीआर अपनी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेजता है, ताकि उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।

मंत्री ने बताया कि ये मामले सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत दर्ज किए गए हैं और इसमें उन उत्पादों को शामिल किया गया है जो आईपीआर, बीआईएस और एफएसएसआईआई मानकों का उल्लंघन करते हैं। सरकार का उद्देश्य घरेलू उद्योग को सस्ते और घटिया आयात के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। उन्होंने बताया कि व्यापार उद्योग महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग की ओर से दायर याचिकाओं के आधार पर जांच करता है और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत कार्रवाई करता है।

मार्च में सरकार ने 1.96 लाख करोड़ GST वसूला

एजेंसी | नई दिल्ली

नई दिल्ली। सरकार ने मार्च 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 9.9% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार 1 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले यानी मार्च 2024 में सरकार ने 1.78 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्ट किया था। एक महीने पहले यानी जनवरी में सरकार ने GST से 1.84 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, जो पिछले साल फरवरी के मुकाबले 9.1% ज्यादा था। वहीं, मार्च लगातार 13वां महीना रहा, जब मंथली कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में 19.56 लाख करोड़ रुपए नेट GST कलेक्शन हुआ है।

अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ था

ग्राँट टैक्स कलेक्शन के लिहाज से नवंबर महीने में अब तक का तीसरा सबसे बड़ा कलेक्शन रहा था। इससे पहले अप्रैल 2024 में सबसे ज्यादा 2.10 लाख करोड़ रुपए GST के रूप में वसूले गए थे। वहीं, अप्रैल-2023 और अक्टूबर-2024 में 1.87-1.87 लाख करोड़ रुपए का GST सरकार ने वसूला था।

पूंजीगत व्यय में कटौती के बजाय 11.21 लाख करोड़ रुपए निर्धारित

एजेंसी | नई दिल्ली

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती नहीं की गई है, बल्कि इसे बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों में अनुपातिक वृद्धि की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यसभा में एक संवाक का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल

बड़े नक्सल ऑपरेशन में शामिल कमांडो से मिलेंगे गृहमंत्री अमित शाह

एजेंसी | रायपुर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। 4 अप्रैल को वे रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 5 अप्रैल को वे दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक और भोजन करेंगे।

नक्सल ऑपरेशन में शामिल कमांडो से होगी मुलाकात



गृहमंत्री शाह नक्सल अभियान में शामिल कमांडो के साथ बैठक करेंगे और उनकी रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में दी। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर को लाल आंकड़ से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है। अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया है, जो रणनीतिक और तार्किक आधार पर लिया गया निर्णय है।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान घेरा डालकर पकड़ा

एजेंसी | बेतिया

बिहार के बेतिया जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धनहा थाना पुलिस ने अपराध नियंत्रण के तहत सोमवार देर रात एक बड़ी सफलता हासिल की। धनहा और रतवल गौतम बुद्ध सेतु पर चलाए गए सघन वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने तस्करों में संलिप्त एक स्कोर्पियो वाहन को रोका। तलाशी के दौरान उसमें से 1 किलो चरस बरामद किया गया। इसके साथ ही, पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए।



गिरफ्तार तस्करों की पहचान

धनहा थानाध्यक्ष धर्मवीर कुमार भारतीय ने जानकारी दी कि गिरफ्तार तस्कर सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनमें हनुमानगंज थाना क्षेत्र के हनुमानगंज गांव निवासी विजय चौधरी, जटाहा थाना के जटाहा बाजार निवासी अफरीदी, कठार गांव निवासी सुरेंद्र यादव और सदीप कुमार शामिल हैं।

भागने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने घेरा डालकर पकड़ा

थानाध्यक्ष ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान यूपी की ओर से आ रही एक स्कोर्पियो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक ने तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर स्कोर्पियो को दबोक लिया। जब वाहन की तलाशी ली गई, तो उसमें से 1 किलो चरस बरामद हुआ। वहीं, सदीप और विजय चौधरी की तलाशी में एक देसी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस भी मिले।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई, न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

पुलिस ने तस्करों के वाहन को भी जब्त कर लिया और इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में इन तस्करों के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। मंगलवार को चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में बगहा भेज दिया गया।

न्यूज़ ड्रीम

मौका मिला तो दोबारा अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे : बुच विल्मोर

केप केनवैरल। नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने सोमवार को कहा कि उनकी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए कुछ हद तक वे स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह बिना देर किए बोइंग स्टारलाइनर पर दोबारा उड़ान भरेंगे।

कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

नई दिल्ली। राजज एवेन्स अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया और कहा कि इसमें जांच की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कपिल कथित अपराध के समय इलाके में थे। ऐसे में उक्त मामले में आगे की जांच जरूरी है।

सुरंग में नमो भारत की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल

नई दिल्ली। नमो भारत के न्यू अशोक नगर से आनंद विहार तक भूमिगत खंड पर सुरक्षा को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान परखा गया कि अगर सुरंग में आग लगने की घटना हुई तो यात्रियों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इसमें नमो भारत ट्रेन की ऑपरेशन टीम, क्यूआरटी और दमकल विभाग की टीम शामिल रही। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नमो भारत ट्रेन और स्टेशनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। इन इंतजामों को परखने के लिए न्यू अशोक नगर और आनंद विहार भूमिगत स्टेशन के बीच यात्री सुरक्षा मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया गया।

नगालैंड के एक और जिले में अफस्यु लागू

केन्द्र सरकार ने नगालैंड के मेलेरु जिले में छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्यु) मंगलवार को लागू कर दिया। इससे दो दिन पहले ही राज्य के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्यु लागू किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि नगालैंड सरकार ने नवंबर 2024 में फेक जिले से मेलेरु जिले का निर्माण किया था, लेकिन 30 मार्च को सात अन्य जिलों के साथ इसे भी अंशतः क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इस कारण यहां अफस्यु लागू किया जा रहा है। अफस्यु अंशतः क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां देता है और केंद्र की मंजूरी के बिना उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है।

साबरमती आश्रम पर तुषार गांधी की याचिका स्वारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ दायर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका दायर करने में दो साल से अधिक की देरी का उल्लेख करते हुए कहा कि वह याचिका में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। तुषार ने गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ अपनी याचिका में तर्क दिया था कि प्रस्तावित परियोजना आश्रम की आकृति को बदल देगी। याचिका में कहा गया है कि परियोजना में कथित तौर पर 40 से अधिक इमारतों की पहचान की गई है जिन्हें संरक्षित किया जाएगा जबकि शेष लगभग 200 को नष्ट कर दिया जाएगा। या उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने 2022 में तुषार की याचिका का उस समय निपटारा कर दिया था, जब सरकार ने कहा था कि आश्रम का मुख्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने 1917 में स्थापित किया था।

सुरंग में नमो भारत की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल

नई दिल्ली। नमो भारत के न्यू अशोक नगर से आनंद विहार तक भूमिगत खंड पर सुरक्षा को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान परखा गया कि अगर सुरंग में आग लगने की घटना हुई तो यात्रियों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इसमें नमो भारत ट्रेन की ऑपरेशन टीम, क्यूआरटी और दमकल विभाग की टीम शामिल रही। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नमो भारत ट्रेन और स्टेशनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। इन इंतजामों को परखने के लिए न्यू अशोक नगर और आनंद विहार भूमिगत स्टेशन के बीच यात्री सुरक्षा मॉक ड्रिल आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोड़रा की याचिका खारिज की

एजेंसी | नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी सांसद महुआ मोड़रा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक निवेश जोन और विदेशी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का सार्वजनिक खुलासा अनिवार्य करने की मांग की गई थी।

लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल

एजेंसी | नई दिल्ली

वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) ने जब इस बात की जानकारी दी, तब विपक्ष ने कहा कि चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने BAC की बैठक से वाकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोरोई ने सरकार पर अपने एजेंडे को थोपने और विपक्षी सदस्यों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल पर मंगलवार को भी लोकसभा में हंगामा हुआ। प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी।

संसदीय कार्य मंत्री बोले- देश जानना चाहता है किसका क्या स्टैंड

भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने सांसदों को सदन में पूरे समय मौजूद रहने को कहा है। वहीं, कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को बजट सत्र के बाकी बचे तीनों दिन सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम बिल पर चर्चा चाहते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इस पर बोलने का अधिकार है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। अगर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होना चाहता तो हम उन्हें रोक नहीं सकते।



हर अच्छे काम का विरोध होता है, इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है, जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जे का माध्यम बन गया है।

-योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

पिछले 75 साल से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए फर्जी कहानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम मुसलमान लुब्धक नहीं चाहते, वे सशक्तिकरण चाहते हैं। वक्फ बिल से सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को होगा।

-मिलिंद देवड़ा, शिवसेना के राज्यसभा सांसद

वक्फ संशोधन बिल को 'वक्फ बर्बाद बिल' कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील की कि उन्हें सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए कि वे क्या करवाना चाहते हैं।

-असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख

भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है। भाजपा पूरा नियंत्रण चाहती है। प्रशासन के गलत फैसले के कारण भारत की संस्कृति और भाईचारे के खिलाफ खाई पैदा की गई है। वह कहते थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्या भाजपा ईद पर किट बांटकर तुष्टीकरण नहीं कर रही है? अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट

एजेंसी | बनारसकांठा

गुजरात के बनारसकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग हादसे में 20 श्रमिकों की मौत हो गई है। हादसे में मृतक श्रमिकों में सभी मध्य प्रदेश के मजदूर बताए जा रहे हैं। इसमें हरदा जिले के हंडिया के रहने वाले आठ और छह देवास के मजदूरों की पहचान हुई है। मृतकों में बाकी छह लोगों की अभी पहचान होना बाकी है। हरदा जिला प्रशासन ने एडीएम के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। इसके लिए प्रशासन और पुलिस को एक टीम को हरदा से बनारसकांठा रवाना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात के बनारसकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से मध्यप्रदेश निवासी श्रमिकों के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का गुजरात सरकार से घटना के संबंध में लगातार संपर्क बना हुआ है। श्रमिकों की सहायता और परिवारों

एमपी के 20 मजदूरों की मौत

सीएम ने जताया गहरा दुख

मैं इस दुर्घटना में राहत, बचाव और उपचार कार्य के संबंध में प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हूँ। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायलों को जल्द से जल्द उचित उपचार मिले। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की मदद देगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मृत कर्मचारियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे।

-भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री

गुजरात सरकार के परिवार के लिए किया मुआवजे का ऐलान

गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम मोहन यादव ने भी घटना पर दुख जताया है। सीएम यादव के मुताबिक उनकी सरकार गुजरात सरकार से संपर्क में है और हादसे के हातहतों को उचित आर्थिक मदद दिया जाएगा।

नहीं रहे प्रेमचंद के बाँसवेल

प्रख्यात साहित्यकार डॉ. कमल किशोर गोयनका का निधन

एजेंसी | नई दिल्ली

हिन्दी के प्रख्यात लेखक और उपन्यास सम्राट् मृंगी प्रेमचंद के साहित्य के सर्वोत्तम विद्वान शोधकर्ता डॉ. कमल किशोर गोयनका का मंगलवार को निधन हो गया। उनके बेटे संजय ने बताया कि उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में सुबह लगभग 7:30 अंतिम सांस ली। उनके छोटे पुत्र राहुल विदेश में हैं। इसलिये उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा।



24वें व्यास सम्मान से अलंकृत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 11 अक्टूबर 1938 को जन्मे कमल किशोर गोयनका को वर्ष 2014 के लिए 24वें व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक 'प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन' के लिए दिया गया था। उन्हें व्यास सम्मान के साथ-साथ उदय राज स्मृति सम्मान भी प्राप्त था। उन्हें प्रेमचंद साहित्य का अप्रतिम मर्मज्ञ माना जाता है। उनका योगदान केवल प्रेमचंद तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हिंदी साहित्य के गम्भीर शोध, आलोचना और प्रवासी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी असाधारण कार्य किया।

62 पुस्तकों में से 36 प्रेमचंद पर केंद्रित डॉ. गोयनका चार दशक तक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी के शिक्षक रहे और रीडर पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने पांच दशक से अधिक समय तक प्रेमचंद और अन्य लेखकों पर शोध किया। उनकी 62 पुस्तकों में से 36 प्रेमचंद पर केंद्रित हैं। वे 'प्रेमचंद के बाँसवेल' के रूप में विख्यात हुए। उनकी खोजी दृष्टि ने प्रेमचंद साहित्य की दशकों पुरानी धारणाओं को युनैती दी और भारतीयता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद की पुनर्वाख्या की। उन्होंने हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक खोज का कार्य किया और लगभग एक हजार पृष्ठों के अज्ञात एवं दुर्लभ साहित्य, सैकड़ों मूल दर्तावेज, पत्र, पांडुलिपियां आदि को खोजकर प्रेमचंद के साहित्यिक स्वरूप

रणवीर अल्लाहाबादिया और आशीष चंचलानी को नहीं मिली राहत

जांच पूरी होने तक पासपोर्ट देने से इनकार

एजेंसी | नई दिल्ली

यूट्यूबर रणवीर अल्लाहाबादिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने शो में शालीनता बनाए रखने की बात कही। रणवीर ने अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई इंटरव्यू के सिलसिले में उन्हें विदेश जाना पड़ता है और कई मीटिंग करनी पड़ती है। रणवीर ने तर्क दिया कि इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर वह विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित होगी। रणवीर अल्लाहाबादिया के अलावा आशीष चंचलानी ने भी अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन शीघ्र अदालत ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया।



कब तक चलेगी जांच?

पीठ ने कहा कि अगर अल्लाहाबादिया विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित होगी। साथ ही महाराष्ट्र और असम सरकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच पूरी करने की समय-सीमा के बारे में भी पूछा। तुषार मेहता ने जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना जताई। पीठ ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद पासपोर्ट जारी करने के अल्लाहाबादिया के अनुरोध पर विचार करेगी।

शर्तों के साथ शो शुरू करने की अनुमति

'इंडिया गॉट टैलेंट' में अश्लील और विवादास्पद बयान के विवाद में फंसे रणवीर को 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उनका पॉडकास्ट 'द रणवीर शो' फिर से शुरू करने की अनुमति दी। यह अनुमति उन्हें नैतिकता और शालीनता बनाए रखने और सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाने के शर्त पर मिली। रणवीरसमय रेना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' पर माता-पिता को लेकर अश्लील टिप्पणी की थी।

येशु-येशु वाले बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद

एजेंसी | मोहाली

रेप केस में दोषी करार दिए गए स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रान्त कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बजिंदर सिंह खुद को धार्मिक प्रचारक बताते हैं और अपनी सभाओं में चमत्कार करने के दावे करते रहे हैं। कई बार उनको सभाओं में सिलेब्रिटीज भी शामिल हुए। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में वह लगातार विवादों में घिरे रहे और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए।

कैसे खुला मामला?

यह मामला 2018 में जैरकपुर पुलिस थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से सामने आया था। महिला ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का झांसा दिया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने घर पर बलात्कार किया।

किस धाराओं में दोषी करार?

अदालत ने बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाने), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। सजा सुनाए जाने के बाद 42 वर्षीय पादरी को पटियाला जेल भेज दिया गया। इस केस में पांच अन्य आरोपी अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, रितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया, जबकि ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

चिंताजनक अंतरराष्ट्रीय नेत्र सम्मेलन में विशेषज्ञों ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त की

बच्चों की आंख खराब और बड़ों में माइग्रेन की वजह बन रही रील्स

एजेंसी | नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर बढ़ती रील्स देखने की आदत अब केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि आंखों के लिए भी गंभीर खतरा बन रही है। डॉक्टरों और नेत्र रोग विशेषज्ञों ने हाल ही में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक रील्स देखने से डार्क आई सिंड्रोम, मायोपिया (नजदीक की दृष्टि कमजोर होना), आंखों में जलन, धुंधली दृष्टि और भेगापन जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं।



डिजिटल आई स्ट्रेन की महामारी

द्वारका में आयोजित प्रेस वार्ता में एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्टोमेट्रोलॉजी के अध्यक्ष डॉ. ललित वर्मा ने इसे डिजिटल आई स्ट्रेन की महामारी करार देते हुए चेतावनी दी कि बच्चों और युवाओं में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार,

50 फीसदी आबादी पर मायोपिया का खतरा 2050 तक दुनिया की 50 फीसदी आबादी मायोपिया से पीड़ित हो सकती है। पहले 21 साल की उम्र के बाद चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता था, लेकिन अब 20 साल तक की उम्र में भी चश्मे का नंबर बढ़ जा रहा है।

ये उपाय अपनाएं

हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर देखें स्क्रीन के सामने पलकें झपकाने की आदत जरूर डालें रील्स और स्क्रीन टाइम सीमित करें

पूर्व अध्यक्ष डॉ. हरवंश लाल ने बताया कि जो लोग रोजाना घंटों तक रील देखते हैं, उनमें शुरुआती मायोपिया विकसित होने का खतरा अधिक होता है। वयस्क में भी नीली रोशनी के अधिक संपर्क से सिरदर्द, माइग्रेन और नींद की समस्या बढ़ रही है।